

॥ श्री ॥

५७. R PBR/2018
 प्रतुति दिनांक: 11/06/2018

(61)

:: न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष नृसिंह राजपूत, जेडल ब्लू मंगलपुर म.प्र. ::

किराानी-3549/2018/धार/भू.रा

रतनसिंह पिता धनसिंहजी चावड़ा ,आयु ६६ वर्ष,
 जाति राजपूत, व्यवसाय कृषि, निवासी राजपुरा
 हाल मुकाम ग्राम अमझैरा, तहसील सरदारपुर, जिला
 धार ॥ मध्य- प्रदेश ॥ :-- निगरानीकर्ता
 ॥बनाम॥
 शासन :-- विपक्षी

मि. सी. उपा
 या आज दि. 11-6-18 को
 प्रस्तुत। प्रारम्भिक कार्य के
 दिनांक 04-7-18 नियत।
 क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-6-18
 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मि. सी. उपा
 (2-2-05)
 11-6-18

:: निगरानी अर्ज धारा ५० भू. राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत ::

मान्यवर महोदय,



श्रीमान् की सेवा में अत्यन्त विनम्रतापूर्वक अर्ज है कि, ग्राम अमझैरा तहसील सरदारपुर की आबादी भूमि सर्वे नम्बर -५५५५ जिसमें अनेक व्यक्तियों के मकानात मौके पर बने हुवे है, इस भूमि में से ३०x४० वर्गफीट का एक भूखण्ड विधीवत न्यायालय तहसील सरदारपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक १७४-बी-१२१/२०१४-१५ में विधी अनुसार जांच कर १२x१० वर्गमीटर का उल्लेख करते हुवे चतुरसोमा का उल्लेख करते हुवे विधीवत भूखण्ड का भूमि स्वामी अधिकार निगरानीकर्ता को बाद् जांच प्रदान किया गया है, उसके ताबे निगरानीकर्ता ने तत्काल ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज कराकर उस पर निमर्ण करने के लिये निमर्ण अनुमति ग्राम पंचायत अमझैरा से माँगी तो ग्राम पंचायत अमझैरा ने पत्र क्रमांक ४८७/ग्राम पंचायत / २०१७ में आदेश दिनांक ३०.१.२०१७ व्दारा भूखण्ड पर निमर्ण के लिये अनुमति प्रदान की और उसी समय निगरानीकर्ता ने उस पर लाखों रूपया खर्च कर मकान का निमर्ण कर लिया है, जिसका उपभोगव उपयोग निगरानीकर्ता करताचला आ रहा है, उक्त मकानवभूखण्ड के संबंध में किसी मुत्फरिक शिकायती अर्जी पर से जो किसी हमसे रंजिश रखने वाले पत्रकार के व्दारा की गई है, उसके ताबे नायब तहसीलदार महोदय, तहसील सरदारपुर ने पट्टा निरस्तोकरण

(Handwritten signature)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3549/2018/धार/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
13-02-19	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री टी0टी0गुप्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-4-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p>	<p> अध्यक्ष</p>